

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 17 ● भोपाल ● 1-15 फरवरी, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

जनता और सरकार के एक साथ खड़े होने से तरक्की के मुकाम पर पहुँचा मध्यप्रदेश

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने प्रदेशवासियों को कर्तव्य निर्वहन का संकल्प दिलाया



भोपाल। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने भोपाल के लाल परेड मैदान पर हुए राज्य-स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि मध्यप्रदेश तरक्की के जिस मुकाम पर है, वह प्रदेश की जनता और सरकार के एक साथ खड़े होने से संभव हुआ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश की आगे की यात्रा और समृद्ध तथा सुखद होगी। राज्यपाल ने नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ भी दीं।

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि राज्य सरकार के सुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन का ही नतीजा है कि मध्यप्रदेश की विकास दर देश की औसत विकास दर से अधिक है। उन्होंने कहा कि डेढ़ दशक पूर्व तक मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने भोपाल के लाल परेड मैदान पर हुए राज्य-स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि मध्यप्रदेश तरक्की के जिस मुकाम पर है, वह प्रदेश की जनता और सरकार के एक साथ खड़े होने से संभव हुआ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश की आगे की यात्रा और समृद्ध तथा सुखद होगी। राज्यपाल ने नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ भी दीं।

गिना जाता था। प्रदेश की विकास दर तो कुछ वर्षों तक नकारात्मक भी रही और देश की औसत विकास दर से हमेशा नीचे होती थी। आज मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और विकास दर पिछले एक दशक से दो अंकों के करीब रही है। कृषि विकास दर तो 18 से 20 प्रतिशत तक प्रति वर्ष हो रही है। प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है और प्रति व्यक्ति आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। राज्यपाल ने कहा कि विकास दर न केवल अधिक रहे, बल्कि वह समावेशी भी हो। विकास में गरीबों की भी उतनी ही भागीदारी हो, जितनी बड़े लोगों की हो। राज्य की समावेशी विकास नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गरीबों के लिये रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार की महत्वाकांक्षी योजनाएँ चलाई हैं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा

कि प्रदेश में दीनदयाल गरीब कल्याण वर्ष मनाते हुए सरकार ने प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5.50 करोड़ से अधिक जनसंख्या तक एक रुपये प्रति किलो के मूल्य पर अनाज पहुँचाया गया है। शहरों में दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को 5 रुपये में स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार ने प्रत्येक गरीब को छत मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर रहने वाले 27 लाख ग्रामीणों को अभी तक भू-अधिकार-पत्र दिये जा चुके हैं। सभी पात्र बेघर परिवारों को आवास के लिये भूखण्ड उपलब्ध के लिये प्रदेशभर में भूखण्ड अधिकार अभियान शुरू किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं में 17.50 लाख से अधिक आवास बने

हैं और अगले साल तक 15 लाख आवास बनाये जायेंगे। शहरी क्षेत्रों में इस वर्ष के अंत तक 5 लाख आवास तथा वर्ष 2022 तक 10 लाख आवासीय इकाइयाँ बनाने का लक्ष्य है।

राज्यपाल श्रीमती आनंदबेन पटेल ने महिलाओं के स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआँ-रहित रसोई मिली है। प्रदेश में प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना से 31 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं। राज्य सरकार द्वारा निःशक्तजन, वृद्धजन, निराश्रितों, कन्याओं एवं विधवा परित्यक्ताओं के लिये संचालित कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंगल क्लिक से 36 लाख पेंशनरों के खातों में प्रति माह एक तारीख को 116 करोड़ की वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। स्कूल शिक्षा से जन-समुदाय को

जोड़ने के लिये मिल-बाँचे मध्यप्रदेश कार्यक्रम एक लाख से अधिक शालाओं में चलाया गया। पिछले 10 वर्षों में राज्य में हाई स्कूलों की संख्या पौने तीन गुना और हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या ढाई गुना से भी अधिक हुई है। शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिये निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक, छात्रवृत्ति, सिला हुआ गणवेश और साइकिल जैसी सुविधाएँ दी जा रही हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के पहले वर्ष में ही 28 हजार से ज्यादा बच्चों को स्नातक शिक्षा के लिये लाभ दिया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में कमी को दूर करने के लिये पढ़ाने वालों की केवल एक ही श्रेणी बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा की पहुँच दुर्गम इलाकों तक सुनिश्चित करने के लिये पिछले वर्ष 15 नये कॉलेज और 3 नये मॉडल कॉलेजों की स्थापना की गई है।

स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बाल मृत्यु दर में पिछले एक वर्ष में सर्वाधिक 10 अंकों की कमी

(शेष पृष्ठ 6 पर)

श्री महेश कोरी जी को राज्य मंत्री का दर्जा

भोपाल। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज के अध्यक्ष श्री महेश कोरी को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षण

सहकारिता में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के विक्रेताओं हेतु तीन-तीन दिवसीय प्रशिक्षण 4 सितम्बर 2017 से प्रारंभ किये गये हैं। सहकारी क्षेत्र में देश में यह प्रथम प्रयास है। यह प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर में संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षणों की चित्रमय झलकियाँ।

सत्र क्र. 17 भोपाल



सत्र क्र. 18 भोपाल



सत्र क्र. 16 इंदौर



सत्र क्र. 17 इंदौर



सत्र क्र. 18 इंदौर



सत्र क्र. 16 जबलपुर



सत्र क्र. 17 जबलपुर



सत्र क्र. 18 जबलपुर



कुशल सहकारिता : सफल सहकारिता

उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर जिला स्तर पर सेमीनारों का आयोजन

सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ के निर्देश पर प्रदेश के 51 जिलों में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर प्रदेश में जिला स्तर पर सेमीनार आयोजन का अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न जिलों में 2 जनवरी से इन सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है।

हरदा



हरदा। किसान अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से करवाये व रासायनिक उर्वरक का उपयोग आवश्यकता अनुसार करें। मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना व कम्पोस्ट व जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। यह बात कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र हरदा डॉ. आर.सी. शर्मा ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. होशंगाबाद मुख्य शाखा हरदा में दिनांक 17.01.2018, को आयोजित सेमीनार में कही। सेमीनार का आयोजन म.प्र. राज्य

सहकारी संघ मर्या. भोपाल के मार्गदर्शन में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर द्वारा सहकारी बैंक के सहयोग से सम्पन्न हुआ। डॉ. आर.सी. शर्मा ने कृषकों की समस्याओं का समाधान करते हुये उन्हें जमीन में पोषक तत्व का महत्व जीवाणुओं का संरक्षण खाद व कीट नाशक संतुलन एवं अधिक उत्पादन, लागत में कमी के उपायों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। केन्द्र के व्याख्याता श्री निरंजन कुमार कसारा ने संगोष्ठी के उद्देश्य व महत्व पर प्रकाश डालते हुये सहकारी ऋण साख-सीमा ऋण

के जमा कराने की अवधि सहकारिता से सरोकार के जरिये समाज के सर्वांगीण विकास पर जानकारी प्रदान की। संगोष्ठी प्रारम्भ में अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया संचालन व्याख्याता श्री निरंजन कुमार कसारा ने किया व प्रशिक्षक श्री कालका श्रीवास्तव ने आभार प्रदर्शन किया। बैंक के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री के.सी. सारन द्वारा बैंक की ऋण नीति व वसूली के महत्व की जानकारी प्रदान की।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ में श्री रंजन द्वारा ध्वजारोहण



भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मुख्यालय परिसर में प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। आपने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए अपने कर्तव्य निर्वहन लगन व निष्ठा से करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर राज्य सहकारी संघ के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

के उत्तर दिये, तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के व्याख्याता श्री गणेश प्रसाद मांझी द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी संघ की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए मंच का संचालन किया। इन्दौर प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षक

श्री कालका श्रीवास्तव ने जैविक खाद एवं सौर ऊर्जा की जानकारी प्रदान की। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., गुना के प्रभारी विपणन अधिकारी श्री मनोज कुमार ठाकुर ने सभी का आभार व्यक्त किया।

गुना

गुना। दिनांक 22.01.2018 को म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित,भोपाल एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना के संयुक्त तत्वाधान में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. गुना में सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर उपायुक्त सहकारिता के मार्गदर्शन अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या, गुना के सभागृह में रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर सेमीनार का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कृषि विज्ञान केन्द्र के डॉ.बी.पी.एस. जादौन ने पौधों के पोषक तत्व, मिट्टी का नमूना लेने के तरीके एवं लेने की अवधि



व किसानों के प्रश्नों के उत्तर दिये। साथ ही कृषि विभाग के सहायक संचालक श्री राजवीर सिंह तोमर ने विभिन्न रबी फसलों में जीवाणु खाद की मात्रा प्रति

हेक्टर में जानकारी दी व प्रमुख खरीफ व रबी फसलों हेतु आवश्यक उर्वरकों की मात्रा के रूप में फसलवार जानकारी प्रदान की एवं किसानों के प्रश्नों

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल

(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)

ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039

फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160

Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in, cmctcbpl@rediffmail.com

उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर जिला स्तर पर सेमीनारों का आयोजन

सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ के निर्देश पर प्रदेश के 51 जिलों में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर प्रदेश में जिला स्तर पर सेमीनार आयोजन का अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न जिलों में 2 जनवरी से इन सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है।

देवास



देवास। म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्या, भोपाल व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या, देवास के सहयोग से देवास जिले की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के किसानों के लिये उर्वरक के संतुलित उपयोग पर कार्यशाला देवास में आयोजित की गई। जिसमें मुख्य रूप से कृषकों से डॉ.

अशोक गुप्ता व के.एन. सिंह द्वारा उर्वरकों का संतुलित उपयोग मिट्टी परिक्षण व जैविक खेती की विस्तार से जानकारी दी गई। जिला सहकारी बैंक से प्रबंधक श्री पी.एस. पुरी, श्री एस.एन. नायक व श्री सौलंकी उपस्थित रहे व कृषि विभाग देवास से श्री दिनेश परमार द्वारा कृषि से संबंधित जानकारी

दी गई। कार्यक्रम में देवास जिले की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी कृषक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की रुपरेखा पर व्याख्याता श्री दिलीप मरमट द्वारा प्रकाश डालते हुये कार्यक्रम का संचालन किया गया व प्रशिक्षक श्री हरज्ञान सिंह द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत जबलपुर में प्रशिक्षण

जबलपुर। इन दिनों मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या, भोपाल द्वारा एन.एस.डी.सी. नई दिल्ली के सहयोग से राज्य स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत कमशः तीन दिवसीय सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी क्रम में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन की दिशा में RPL (रिटेल) प्रशिक्षण के अन्तर्गत जनवरी माह का तृतीय सत्र सम्पन्न किया गया। केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने प्रशिक्षण के दौरान "कुशल सहकारिता, सफल सहकारिता" के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। केन्द्र के व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे ने सहकारी समितियों के लिये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए आर.पी.एल. की विस्तृत जानकारी प्रदान की। व्याख्याता श्री बर्वे ने क्रेडिट सेवा, स्टोर, ग्राहक सेवा, प्रोडक्ट प्रदर्शन, विशेषज्ञ सेवा, संस्था के प्रति सकारात्मक छवि, ग्राहक संबंध में सेवा, टीम का प्रभावीकरण, संगठन को सशक्त बनाने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया। एन.एस.डी.सी. के परीक्षक श्री नितिन वर्मा द्वारा सत्र के पश्चात् परीक्षा ली गई।

उल्लेखनीय है कि इस सत्र में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सिंगरोली से संबंधित जिले की लेम्स/पेक्स सहकारी समितियों के विक्रेताओं ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

नवज्योति महिला सहकारी साख समिति की बनाई चूड़ियाँ बेचते हैं व्यापारी

भोपाल। जनपद पंचायत जतारा ग्राम बिजरावन जिला टीकमगढ़ निवासी सुनीता पत्नी हरपाल सिंह परिवार में आय के सीमित साधन होने के कारण परेशान रहती थीं। आत्मनिर्भर बनने के लिये सुनीता गाँव में म.प्र. दीनदयाल अन्त्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित बगाज माता स्व-सहायता समूह में शामिल हुई। उन्हें अपने कार्य और लगन के कारण सीएमटी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, जिसमें इन्होंने आस-पास के कई ग्रामों में समूह गठन का कार्य किया। इसके बाद सुनीता राजा ने व्यवसायिक गतिविधि की योजना बनाई।

सुनीता ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक दिगौड़ा से 50 हजार रुपये का ऋण लेकर ग्राम बिजरावन में मनहारी की दुकान खोली। इससे रोज की आमदानी 300-400 रुपये तक होने लगी। दुकान की सफलता ने हौसला बढ़ाया तो अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई। सुनीता नवज्योति महिला बहुउद्देशीय सहकारी साख समिति मर्यादित दिगौड़ा की सदस्य बनीं और क्लस्टर स्तर की गतिविधि करने की योजना बनाई। कच्ची चूड़ी में पेंटिंग, डिजाइन, कड़े बनाने का कार्य करने का निर्णय लिया तथा फिरोजाबाद का एक्सपोजर भ्रमण कर चूड़ी बनाने की ट्रेनिंग ली।

ग्राम विकास में दुग्ध सहकारिता की अहम भूमिका- श्री वर्मा

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सचिवों का एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण सम्पन्न

सीहोर। जिला सहकारी संघ मर्यादित सीहोर के तत्वाधान में जिले की 40 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सचिवों का एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण जिला संघ कार्यालय भोपाल नाके पर आयोजित किया गया। श्री धरमसिंह वर्मा अध्यक्ष जिला सहकारी संघ मर्यादित सीहोर, श्री के.एस. किरार सेवानिवृत्त आडिट ऑफिसर सहकारिता विभाग द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। उपस्थित अतिथियों का स्वागत तेजसिंह ठाकुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी संघ द्वारा पुष्पमालाओं से किया गया।

धरमसिंह वर्मा अध्यक्ष जिला सहकारी संघ द्वारा सम्बोधित करते हुए कहा कि जिले में

संचालित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से किसान हित जुड़ा हुआ है। दुग्ध उत्पादन से किसान का भविष्य सुधर सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। साथ ही कहा कि स्वच्छ दूध उत्पादन पर बल दिया जावे एवं दूध की गुणवत्ता में सुधार हेतु सभी को प्रशिक्षण विशेष दिया जा सकता है। ग्राम विकास में दुग्ध सहकारिता की एक अहम भूमिका है।

दुग्ध समितियों के सचिवों को संबोधित करते हुए श्री के.एस. किरार द्वारा कहा गया कि कार्यालय की सभी पंजी हमेशा नियमित रूप से अंकित करें। लेनदेन, केशवुक, वाउचर फाइन कार्यालय में रखें/संचालक मण्डल की बैठक प्रति तीन माह में आवश्यक रूप से करें।



इस अवसर पर विशेष रूप से श्री राजेश गौर अध्यक्ष स्थाई कृषि समिति जिला पंचायत सीहोर, श्री शेख मुंशी पत्रकार, आशीष गुप्ता पत्रकार, भगतसिंह तोमर,

रामनारायण चौधरी डेरी प्रमुख, प्रदेश सहकारी भारती, जगदीश चन्द्रवंशी जिला अध्यक्ष सहकारी भारती, पंकज कुमार गौर पर्यवेक्षक, रघुवीर सिंह दांगी,

किसान कांग्रेस प्रदेश सचिव, शादीलाल, छगनलाल पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। आभार तेजसिंह ठाकुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रगट किया गया।

किसानों को उपार्जित गेहूँ का भुगतान सरलता से मिले : श्री चौहान

मुख्यमंत्री ने की उपार्जन व्यवस्थाओं की समीक्षा



भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उपार्जित गेहूँ की राशि का भुगतान अविलंब और सहजता से मिलना चाहिये। किसानों को भुगतान प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत और देरी नहीं हो। श्री चौहान

आज मंत्रालय में गेहूँ उपार्जन की अग्रिम तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने गेहूँ खरीदी, परिवहन, भंडारण और भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने

कहा कि गेहूँ उपार्जन का कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और परिपूर्णता के साथ हो। उपार्जन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अथवा व्यवधान उत्पन्न नहीं होने पाये। उपार्जन से संबद्ध सभी एजेंसियाँ समन्वय और सामंजस्य के साथ समय-सीमा में

अग्रिम तैयारियाँ कर लें। उपार्जन अवधि में वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों में पर्याप्त नगदी की उपलब्धता रहे। ग्रामीण अंचल में भंडारण का अग्रिम आकलन कर स्थानीय बैंक शाखाओं में आवश्यकतानुसार नगदी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। उन्होंने बैंक अधिकारियों से इस संबंध में अग्रिम व्यवस्थाएँ करने को कहा। साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को उपार्जन के लिये भुगतान की अनुमानित राशि की आवश्यकता और उपलब्धता की जानकारी बैंकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने अनुमानित आवक के अनुसार बारदानों का

अग्रिम भंडारण करने के लिये कहा। उन्होंने निर्देश दिये कि खरीदी केन्द्र से भंडार गृह तक उपार्जित गेहूँ परिवहन की व्यवस्थाएँ समय-सीमा में करने की प्रक्रिया अपनायें। परिवहन कार्य की व्यवस्थाएँ पारदर्शी हों और उसकी सतत् मानीटरिंग की जाये। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 50 लाख बारदाने उपलब्ध हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल और बैंक अधिकारी उपस्थित थे।

हजारों बाइकों के साथ राज्य मंत्री श्री सारंग ने निकाली तिरंगा यात्रा

भोपाल। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने हजारों बाइकों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में ट्राईकलर पगड़ी पहने और हाथों में तिरंगा थाम सभी वर्गों तथा समुदाय के लोगों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा में तीन कतारों में बाइक सवार पूरी तरह अनुशासित होकर चल रहे थे। सहकारिता राज्य (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री श्री विश्वास सारंग मोटर साइकिल पर सवार होकर पूरी यात्रा में चले। तिरंगा यात्रा बुद्ध विहार अन्ना नगर से प्रातः 11.00 बजे शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से होकर शाम को दुर्गाधाम मंदिर पर समाप्त हुई। गणतंत्र दिवस के पूर्व दिवस पर आयोजित तिरंगा यात्रा का 68 स्थानों पर तिरंगा यात्रा के भव्य स्वागत हुआ। पूरे यात्रा मार्ग में नागरिकों ने मानव श्रृंखला बना पुष्पवर्षा से तिरंगा यात्रा का स्वागत किया।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि राष्ट्र प्रेम, देश भक्ति की भावना जगाने और निष्ठावान अनुशासित, समर्पित नागरिक के मूल्यां की प्रेरणा देने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा की वर्तमान पीढ़ी आजादी और देशप्रेम के मूल्यां को समझे और आत्मसात करे। यात्रा में स्वप्रेरणा से स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया।



सायबर जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन



इन्दौर। सहकारिता जगत में सायबर अपराध तथा उससे बचाव व कानूनी पहलू पर म.प्र. राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा प्रारम्भ सायबर जागरूकता अभियान अंतर्गत जनवरी माह में इन्दौर जिले के सहकारिता विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु कार्यशाला का

आयोजन श्रम शिविर, इन्दौर स्थित कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त सहकारिता इन्दौर श्री के. पाटनकर तथा सहायक आयुक्त श्री सुरेश सांवले उपस्थित रहे। प्रशिक्षण श्री शिरीष पुरोहित, कम्प्यूटर प्रशिक्षक, इन्दौर द्वारा दिया गया। इसी कड़ी में धार जिले के

सहकारिता विभाग के अधिकारियों व सहकारी समितियों के कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के लिये प्रशिक्षण होटल रुद्राक्ष, जेतपुरा, धार में आयोजित किया गया। इसमें कुल 104 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री आर. एस.

वसुनियां, धार जिले के उपायुक्त श्री अम्बरीष वैद्य तथा जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री विरेन्द्रसिंह पंवार उपस्थित रहे।

इसके पश्चात जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, धार की शाखाओं के कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के लिये प्रशिक्षण जिला सहकारी संघ, धार में

आयोजित किया गया। प्रशिक्षण श्री शिरीष पुरोहित, कम्प्यूटर प्रशिक्षक, इन्दौर द्वारा दिया गया। इन कार्यशाला की व्यापक सराहना हो रही है। आपके यहां कार्यशाला आयोजन हेतु श्री शिरीष पुरोहित मोबा. 99264 51862 पर सम्पर्क करें।

(पृष्ठ 1 का शेष)

जनता और सरकार के एक साथ खड़े होने से तरक्की के मुकाम पर पहुँचा मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में रिकार्ड हुई है। इन्द्रधनुष योजना में टीकाकरण की दर 74 फीसदी से बढ़कर 90 फीसदी तक हो गई है। सभी 51 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये आगामी शैक्षणिक सत्र से 7 नये मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किये जा रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व से चल रहे मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि की जा रही है। जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में सुपर स्पेशियलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है। प्रथम बोनमेरो ट्रांसप्लांट की स्थापना इंदौर मेडिकल कॉलेज में की गई है।

कुपोषण से निपटने के लिये ठोस प्रयास

राज्यपाल ने कहा कि पिछड़ी जनजातियाँ बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की गई है। प्रत्येक परिवार को एक हजार रुपये प्रति माह का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। राज्य के 15 जिलों की किशोरियों को सबला योजना के तहत टेक-होम पोषण-आहार दिया जा रहा है। राज्य के अति कुपोषित 85 विकासखण्डों में साढ़े 11 लाख स्कूली बच्चों को सप्ताह में तीन दिन गुड़-मूँगफली की चिक्की देने की योजना लागू की जा रही है। राज्य सरकार टेक-होम राशन की वर्तमान व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब टेक-होम राशन की तैयारी कम्पनियों के स्थान पर महिला स्व-सहायता समूहों के जिला-स्तरीय संघ द्वारा की जायेगी।

स्वच्छता अभियान

प्रदेश में प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि 13 जिले और 10 हजार से अधिक ग्राम-पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हुई हैं। प्रदेश में 81 लाख से अधिक घरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने जन-सामान्य से स्वच्छता मिशन में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी ग्रामों को चरणबद्ध तरीके से नल-जल योजना के माध्यम से पीने का साफ

पानी उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके अलावा प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना भी प्रारंभ की गई है। इसके तहत एक हजार तक की आबादी वाले गाँवों को नल-जल योजना से जोड़ा जायेगा।

रोजगार के अवसर

गरीबों के लिये रोजगार और कौशल संवर्धनको जरूरी बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने युवा सशक्तिकरण मिशन के नाम से एक नया मिशन प्रारंभ किया है, जिसके तहत हर साल 7 लाख 50 हजार युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जायेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन से सवा 23 लाख व्यक्तियों को 2 लाख से ज्यादा स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। मिशन द्वारा 6 लाख 25 हजार बेरोजगारों को रोजगार के साथ जोड़ने के साथ-साथ 14 लाख 50 हजार परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में एक लाख 6 हजार हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देकर 52 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को स्व-रोजगार में लाया गया है।

नर्मदा नदी संरक्षण और एकात्म यात्रा

राज्यपाल ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा नदी संरक्षण का संदेश देने वाला अभूतपूर्व अभियान साबित हुआ जो जनता की सक्रिय भागीदारी के कारण सफल हो पाया। संरक्षण अभियान को मूर्तरूप देने के लिये नर्मदा सेवा मिशन के नाम से परियोजना तैयार की गई। प्रदेश में 2 जुलाई को नर्मदा कछार में 6 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गये हैं। नदी के तटों पर 4,500 शांतिधाम बनाये गये हैं और 250 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण किये जा रहे हैं। जिन उद्योगों का पानी नदी में जाता था, उनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और पाइप-लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। एकात्म यात्रा की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह यात्रा सांस्कृतिक एकता के देवदूत अद्वैत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता और सनातन संस्कृति के पुनरुद्धारक आदि शंकराचार्य के एकात्म दर्शन को जन-सामान्य तक पहुँचाने में सफल रही है।

कृषि क्षेत्र में प्रगति

राज्यपाल ने प्रदेश में पिछले 14 साल में कृषि के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में 18 प्रतिशत सालाना से अधिक औसत कृषि विकास दर प्राप्त करने वाला मध्यप्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुना करने के लिये रोड-मेप बनाकर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में फसल भावांतर भुगतान योजना की बदौलत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सोयाबीन, उड़द, मूँग, मूँगफली और मक्का आदि फसलों में मिल पाया है। इस योजना की प्रशंसा राष्ट्रीय-स्तर पर भी की गई है। प्रदेश में किसान भाइयों के प्रयास से उद्यानिकी क्षेत्र का रकबा अब 19 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में पौने तीन लाख मीट्रिक टन प्याज की भण्डारण क्षमता बढ़ाई गई है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में हो रही लगातार वृद्धि की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि दुग्ध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 10.70 प्रतिशत रही है, जो देश की वृद्धि दर से दोगुनी है। खेती का खर्च कम करने के लिये राज्य सरकार ने किसानों को शून्य ब्याज दर का लाभ दिया है। इससे 17 लाख किसानों को लाभ पहुँचा है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिये भी लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। नर्मदा का पानी क्षिप्रा में डालकर और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंग बनाकर पानी ले जाने को भी राज्य सरकार ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। प्रदेश में 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर सिंचित रकबे से बढ़ते हुए सिंचाई की क्षमता वर्ष 2025 तक शासकीय स्रोतों से 60 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य तैयार किया गया है। इस वर्ष अब तक करीब 25 हजार हेक्टेयर क्षमता की 65 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं।

बिजली की उपलब्धता

राज्यपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश आज बिजली के क्षेत्र में न केवल आत्म-निर्भर हुआ है, बल्कि सरप्लस बिजली बेचने की क्षमता भी रखता है। प्रधानमंत्री की सौभाग्य योजना के तहत वर्ष 2018 तक हर घर में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य राज्य

सरकार ने तय किया प्रदेश में जून-2019 तक 5 लाख अस्थाई कनेक्शनों को स्थाई कनेक्शन में बदल दिया जायेगा।

सड़क निर्माण और अमृत योजना

राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क सुधारने के लिये व्यापक प्रयास किये गये हैं। तीन हजार किलोमीटर के नये राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर किये जा चुके हैं। इसके अलावा 2,383 किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्गों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 75 हजार किलोमीटर से अधिक ज्यादा लम्बाई की सड़कों का निर्माण हो चुका है। एक लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहर और पर्यटन शहर ओंकारेश्वर में अमृत योजना में 5 वर्ष में 6,200 करोड़ की राशि व्यय की जायेगी।

अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण

राज्यपाल श्रीमती आनंदबेन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के विकास के लिये एक पंचवर्षीय एकीकृत कार्य-योजना तैयार की गई है। वन अंचल में रहने वाले वनवासियों को करीब ढाई लाख वन अधिकार-पत्र बाँटे जा चुके हैं। अनुसूचित-जाति और जनजाति वर्ग को स्व-रोजगार योजना से जोड़ा जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिये कौशल विकास की योजना चलाई जा रही है। भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के लिये करीब डेढ़ लाख प्रकरण भेजे गये हैं। भोपाल में हज-हाउस बन गया है। वक्फ सम्पत्ति का कम्प्यूटरीकरण जारी है।

महिला सशक्तिकरण

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की महिला सशक्तिकरण की कोशिशें देश में मिसाल बनी हैं। लाइली लक्ष्मी योजना का लाभ 27 लाख बालिकाओं को मिल चुका महिलाओं के लिये अनुकूल वातावरण बनाने में सफल रहे 82 हजार शौर्या दल की प्रशंसा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा की गई है। लाडो अभियान में 83 हजार बाल-विवाह रोकने में सफलता मिली है।

निवेशकों की पहली पसंद

मध्यप्रदेश

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है। ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग में मध्यप्रदेश को वर्ष 2015-16 में

पाँचवीं रैंक मिली है। प्रदेश में 2300 करोड़ की लागत से 22 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य इस वर्ष पूरा हो जायेगा। मध्यप्रदेश में एमएसएमई विकास नीति और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अप्रैल-2018 से प्रभावशील हो जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक शांति की आदर्श स्थिति है।

सुशासन

राज्यपाल ने कहा कि सुशासन राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। समय-सीमा में नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने की कानूनी गारंटी के बाद राज्य सरकार अब इससे एक कदम आगे जा रही है और **समाधान एक दिन** लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिये राज्य न्यायालयों के कार्य में कसावट लायी जा रही है। राजस्व महा-अभियान में 10 लाख अविवादित नामांतरण एवं बँटवारे निराकृत हुए हैं। किसानों को सवा चार करोड़ खसरा एवं खतौनी की नकल निःशुल्क बाँटी गयी है।

पर्यटन एवं संस्कृति

राज्यपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश पर्यटकों के लिये पसंदीदा जगह बन गया है। अब जिला-स्तर पर धार्मिक पर्यटन-स्थलों के विकास की योजना है। हनुवंतिया की तर्ज पर ओंकारेश्वर के नजदीक सैलानी टापू को जल-पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। इस वर्ष गाँधी सागर में जल-महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में बहु-उद्देश्यीय सांस्कृतिक कला-संकुल स्थापित किये गये हैं। स्वाधीनता संग्राम के दस्तावेजीकरण, संग्राम में जन-जातियों की भागीदारी, जन-जातीय चेतना और संघर्ष को रेखांकित करने वाला पहला और अकेला प्रयास मध्यप्रदेश में किया गया है।

वन सम्पदा

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि मध्यप्रदेश वन के मामले में समृद्धशाली राज्य माना जाता है। वनों के संरक्षण और संवर्धन की प्रभावी पहल का ही परिणाम है कि वनों और उन पर आश्रित ग्रामीणों की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये चरण-पादुका योजना प्रारंभ की गई है। योजना से 21 लाख से अधिक संग्राहकों को लाभ होगा।

भावांतर भुगतान योजना देश का रोल मॉडल बनेगी : मुख्यमंत्री

पंजीकृत 32,309 किसानों को 64.03 करोड़ भावांतर राशि का वितरण



भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवाओं में अनंत शक्ति का भंडार होता है। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं, जो युवा नहीं कर सकते। युवाओं को पर्याप्त सुविधाएँ और अवसर मिल जायें, तो वे चमत्कार कर सकते हैं और परिवार, प्रदेश तथा देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री छिन्दवाड़ा में स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित युवा दिवस समारोह एवं भावांतर योजना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री ने भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत 32 हजार 309 किसानों को 64 करोड़ 3 लाख 43 हजार 279 रुपये की भावांतर राशि के भुगतान प्रमाण पत्र प्रदान

किये और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बटन दबाकर किसानों के खाते में राशि जमा करवाई। श्री चौहान ने इस अवसर पर 24.58 करोड़ रुपये लागत की योजनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान राशि के चैक के साथ ही प्रमाण पत्र भी वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रारंभ में गौ-पूजन एवं कन्या पूजन करते हुए कहा कि बेटियाँ भारतीय संस्कृति में देवी तुल्य हैं, बेटों के समान बेटियों का भी सम्मान करें। उन्होंने सरकारी नौकरी में बेटियों को दिये जाने वाले आरक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को

फांसी देने के संबंध में विधानसभा में पारित अधिनियम को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिये भेजा गया है। उन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाने के का जिक्र करते हुए पंच व्यपवर्तन परिवर्तन योजना के संबंध में बताया कि इस परियोजना का परीक्षण कर माईक्रो ईरीग्रेशन के संबंध में सर्वेक्षण कराने के साथ सिंचाई का रकबा भी बढ़ाया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना की सफलता से प्रभावित होकर केन्द्र एवं अन्य राज्यों के दल इस योजना की जानकारी लेने प्रदेश में आ रहे हैं। यह योजना किसानों के लाभ की दृष्टि से पूरे हिन्दुस्तान के लिये रोल मॉडल बनेगी। उन्होंने कहा कि पहले

किसानों को 18 प्रतिशत ब्याज पर कर्जा मिलता था जिसे धीरे-धीरे कम करते हुये अब बिना ब्याज के कर्जा दिया जा रहा है और 10 प्रतिशत कृषि अनुदान भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा में दी जाने वाली सहायता, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति और भावी कार्य योजना की जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों को टेक होम योजना के अंतर्गत भोजन बनाने का कार्य दिया जायेगा। इसके लिये महिलाओं के फेडरेशन का गठन कर उन्हें ऋण सुविधा के साथ ही गारंटी भी दी जायेगी। इस प्रयास से लगभग 250 करोड़ रुपये महिलाओं के खाते में जमा होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब छात्र-छात्राओं को गणवेश सिलवाकर दी जायेगी। इसके लिये भी महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्य में भी उनके खाते में लगभग 250 करोड़ रुपये जमा हो सकेंगे।

कार्यक्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी श्री गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, महापौर श्रीमती कांता सदरंग, भारिया विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला भारती, महाकौशल विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री संतोष जैन, विधायक सर्वश्री चौधरी चन्द्रभान सिंह, नानाभाऊ मोहोड, पं.रमेश दुबे और नत्थन शाह कवरेती, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शैलेन्द्र रघुवंशी, नगर निगम अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र मिगलानी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अध्यक्ष श्री मारोतराव खवसे, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष श्री शेषराव यादव और जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति की सभापति श्रीमती मानवती शाह इवनाती, पिपला-नाराणवार नगर पंचायत अध्यक्ष श्री राजू परमार सहित अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक तथा नगरवासी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से प्रदेश की 58 मण्डियाँ जुड़ीं

किसान को अपनी उपज बेचने का दाम उसी दिन मिल रहा है

भोपाल। प्रदेश के किसानों को अपनी उपज की कीमत सही मिल सके, इसके लिये प्रदेश की 58 कृषि उपज मण्डियों को ई-नाम ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ा गया है। किसान इस व्यवस्था के माध्यम से अपनी कृषि उपज का विक्रय कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में एक ओर जहाँ बोली लगाने वाले व्यापारी की जानकारी गोपनीय होती है, वहीं दूसरी ओर किसान को भी व्यापारियों के मध्य हो रही प्रतिस्पर्धा का लाभ मिलता है। इसमें एक और फायदा यह है कि मण्डी क्षेत्र के बाहर अथवा अन्य मण्डी क्षेत्र का व्यापारी सीधे जिनकी बोली ई-नाम के पोर्टल पर लगा सकता है। इससे किसानों को स्थानीय बाजार के अलावा बाहर के बाजारों का भी लाभ प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)

एक पैन इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि से संबंधित उपजों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिये मौजूदा कृषि उपज मण्डी समिति का एक अच्छा माध्यम है। ई-नाम पोर्टल सभी कृषि उपज मण्डी समितियों से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिये एकल प्रणाली (सिंगल विण्डो) सेवा प्रदान में सक्षम है। इस योजना में अन्य सेवाओं के साथ-साथ मण्डी प्रांगण में कृषि उपज के आगमन और कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।

ई-नाम पोर्टल की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल-2016 में की थी। मध्यप्रदेश में पंडित

लक्ष्मीनारायण शर्मा कृषि उपज मण्डी समिति काँदो, भोपाल में पायलेट योजना से इसकी शुरूआत की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़कर कोई भी कृषि उपज मण्डी राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में भाग ले सकती हैं। किसान जब स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचने के लिये मण्डी में लाते हैं तो स्थानीय व्यापारियों के साथ-साथ इंटरनेट के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में स्थित व्यापारियों को भी अपना माल बेचने का विकल्प उनके पास रहता है। इस व्यवस्था में किसान अपनी उपज को वहीं बेचने के लिये स्वतंत्र होते हैं, जहाँ उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं।

प्रदेश में ई-नाम के पोर्टल को तौल-काँटों से भी जोड़े जाने का कार्य किया जा रहा है।

जैविक खाद से कृषि लागत हुई लगभग शून्य

भोपाल। ग्राम कचनारिया तहसील आगर के किसान गंगासिंह आज आधुनिक तरीक़े से जैविक खेती कर रहे हैं। इस खेती से लागत और मेहनत का भरपूर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब गंगासिंह उन्नत कुषक बन गये हैं।

किसान गंगा सिंह पूर्व में अन्य किसानों की तरह पारम्परिक तरीक़े से खेती कर रहे थे। इससे लागत के अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। इसी बीच आत्मा परियोजना के तकनीकी सहायक श्री वेदप्रकाश सेन के सम्पर्क में आये गंगा सिंह। तब उन्हें कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में मालूम हुआ। इसके बाद गंगा सिंह ने विभाग द्वारा आयोजित जैविक प्रशिक्षणों में भी भाग लिया। प्रशिक्षणों में उन्हें जैविक खाद बनाने की तकनीक का ज्ञान प्राप्त हुआ।

आत्मा परियोजनान्तर्गत गंगा सिंह ने वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण करवाकर जैविक खाद का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। अब जैविक खाद बनाकर स्वयं की खेती में इसका उपयोग कर रहे हैं। इस प्रयोग से गंगा सिंह की कृषि लागत लगभग शून्य हो गई है। फसल भी अधिक मात्रा में क्वालिटी की मील रही है। इस किसान के लिये खेती अब लाभ धन्धा बन गई है।

गंगासिंह अब जैविक खाद तैयार कर स्वयं तो अपनी खेती में उपयोग करते ही हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी जैविक खाद का विक्रय कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं।



गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ

भारत के गणतंत्र की सबसे ऊँची शान
हर भारतवासी को इस पर है अभिमान
गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई
और शुभकामनाएँ

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

गणतांत्रिक मूल्यों के साथ
मध्यप्रदेश

